

भारत सरकार  
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2310  
19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

पीएम ई-बस सेवा (पीएसएम) योजना का कार्यान्वयन

2310 डॉ. कविता पाटीदार:

श्री कणाद पुरकायस्थः  
डॉ. दिनेश शर्मा:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) इस योजना के तहत अब तक तैनात या चालू की गई इलेक्ट्रिक बसों की संख्या सहित पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (घ) आज की तिथि तक संसाधित किए गए भुगतान सुरक्षा समर्थन दावों की कुल संख्या कितनी है और पीएसएम से जारी की गई निधि की मात्रा कितनी है;
- (ग) क्या सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा भुगतान संबंधी गलतियों के कोई मामले सामने आए हैं;
- (घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में किए गए सुधारात्मक उपाय क्या है;
- (ङ) क्या मंत्रालय ने इस योजना के तहत समर्थित इलेक्ट्रिक बसों के प्रचालन निष्पादन, उपयोग दर या सेवा परिणामों का कोई आकलन किया है; और
- (च) यदि हाँ, तो मुख्य निष्कर्ष क्या है?

उत्तर  
भारी उद्योग राज्य मंत्री  
(श्री भूपतिराज् श्रीनिवास वर्मा)

(क): कुल 3,435.33 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम 28 अक्टूबर, 2024 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य 38,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। 15 दिसंबर, 2025 तक, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (डीडीएम) जमा कर दिया है, जोकि इस स्कीम के तहत पात्र होने के लिए एक ज़रूरी शर्त है।

इसके अलावा, सीईएसएल ने 6,198 इलेक्ट्रिक बसों के लिए निविदा आमंत्रित की थी, जिन्हें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम ई-बस सेवा स्कीम के तहत पूरा किया गया था। आज की तारीख तक, सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा 4,472 ई-बसों के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 10,900 ई-बसों के संचालन और रखरखाव के लिए ई-बस संचालकों से सीईएसएल द्वारा आमंत्रित निविदाओं के लिए तकनीकी बोली खोली गई है।

(ख) से (ग): इस स्कीम के तहत कोई चूक संबंधी रिपोर्ट नहीं मिली है और न ही कोई दावा प्राप्त हुआ है।

(घ): भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च): भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत समर्थित इलेक्ट्रिक बसों के प्रचालनात्मक निष्पादन, इस्तेमाल की दरों या सर्विस के परिणामों का ऐसा कोई आकलन नहीं किया है।

\*\*\*\*\*